तमिलनाडु की सरकार ने भाजपा को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी

भाजपा ने अपने स्थापना दिवस पर 51 स्थानों पर रैली निकालने की इजाज़त मांगी थी सरकार से

-लक्ष्मण वैंकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। भाजपा तथा संघ परिवार दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य तमिलनाडु में जी-तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस क्षेत्र से सर्वाधिक लोकसभा सांसद इसी राज्य से चुने जाते हैं। लेकिन ठीक पश्चिम बंगाल, जहाँ भाजपा का सामना ममता बनर्जी जैसी धुरंधर राजनेता से था, यहाँ तमिलनाडु में भाजपा का सामना डी.एम.के. (द्रमुक) प्रमुख तथा लगभग 4 दशकों से प्रादेशिक राजनीति में अहम रोल अदा कर रहे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जैसे धुरंधर नेता से है।

इस समय पार्टी तथा सरकार पर तो स्टालिन का पूरा नियंत्रण है ही, राज्य के 38 में से 29 सांसद उनके पास है जिनमें कांग्रेस सांसद भी शामिल हैं।

जहाँ तक जमीनी स्थिति का प्रश्न है, पिछले विधानसभा चुनावों, जिनमें डी.एम.के. की इकतरफा जीत हुई थी, के बाद, राजनैतिक रूप से कुछ खास परिवर्तन नहीं हुआ है। ए.आई.ए.डी.एम.के. की अंदरूनी लड़ाई के कारण विपक्ष कमजोर ही हुआ है तथा इसके परिणामस्वरूप, भाजपा को विपक्ष में अपने लिये जगह बनाने का अवसर मिल गया है।

तमिलनाडु में इस समय भाजपा को विपक्ष के रूप में लिया जा रहा है तथा इसने जमीनी स्तर पर स्वयं को एक खास अंतर वाली पार्टी के रूप में प्रस्तुत करना शुरु कर दिया है- उसने राजनैतिक हलचल तथा गर्मा-गर्मी के माहौल को स्वरूप देना शुरु कर दिया है। दरअसल, भाजपा तथा पूरा दक्षिणपंथी तंत्र एक विपक्षी दल के रूप में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते तथा ऐसे मुद्दे उठाते हैं, जो हिन्दुत्व एजेंडा की तरफ उनके झुकाव की ओर संकेत करते हैं, जैसे मंदिरों तथा धार्मिक जुलूसों पर अपना नियंत्रण रखने के लिये टकराव या फिर नवीनतम गतिविधि के रूप में, 2 अक्टूबर को 51 स्थानों पर "रूट रैली" (पथ-संचलन) आयोजित करने की आर.एस.एस. की योजना

- **स्टालिन सरकार ने पी.एफ.आई. पर लगे प्रतिबंध के कारण प्रदेश में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने की बात कही और इन हालात में भाजपा को रैलियों की इजाज़त न देने को सही ठहराया।**
- **दूसरी ओर गत सप्ताह ही मद्रास हाई कोर्ट ने भाजपा के 2 अक्टूबर को रैलियां निकालने के प्रस्ताव को सशर्त स्वीकृति दी थी।**

आर.एस.एस. ने अपने स्थापना दिवस महोत्सव पर पथ-संचलन की अनुमति माँगी है।

लेकिन कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुये, पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगाई गई रोक के कारण आर.ए.एस. को इन रैलियों के आयोजन की स्वीकृति देने से इनकार कर दिया है। सरकार ने कहा कि वह ऐसे समय पर किसी पथ-संचलन की अनुमति नहीं दे सकती जब पुलिस पी.एफ.आई. पर लगाई गई रोक के फलस्वरूप किसी भी अप्रिय घटना की संभावना को रोकने के लिये रात-दिन एक कर रही हो। सरकार ने डी.एम.के. के सहयोगी दलों, जैसे वी.सी.के., सी.पी.आई. (एम.) तथा सी.पी.आई. द्वारा सौहार्द्र बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किये जाने वाले कोई भी आयोजन करने की अनुमति नहीं दी है।

एक सरकारी प्रेस-विज्ञप्ति में कहा गया है, "ऐसे समय पर, जब सरकार ऐहतियाती कदम उठाने के अलावा, पूरे राज्य में कानून-व्यवस्था बनाये रखने के लिये सभी प्रकार के प्रयास कर रही है, आर.एस.एस. तथा अन्य संगठनों को 2 अक्टूबर को रैली निकालने के लिये अनुमति देने से इनकार कर दिया गया है।" पी.एफ.आई. पर रोक लगाने के बाद, इस्लामी संगठनों ने इस कार्यवाही के खिलाफ प्रदर्शन करना शुरु कर रहे हैं। पुलिस ने आर.एस.एस. तथा वी.सी.के. को संबंधित आयोजनों के लिये अनुमति देने से इनकार करते हुये, कहा कि इसके अलावा, पिछले कुछ दिनों में, राज्य में, साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाली बहुत सी घटनाएं होती आ रही हैं।

प्रसंगवश बता दें कि पिछले सप्ताह मद्रास उच्च न्यायालय ने कुछ निश्चित शर्तों के साथ, आर.एस.एस. को दो अक्टूबर को जुलूस निकालने की अनुमति दे दी थी। लेकिन सरकार ने, सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुये, अनुमति देने से इनकार कर दिया। वी.सी. के नेता तथा सांसद तोल तिरुमावालानन ने मीडिया कर्मियों को बताया कि "भाजपा, आर.एस.एस. तथा अन्य दक्षिणपंथी ताकतें, सत्ता हासिल करने के लिये, राज्य में हिंसा भड़काने के लिये जानी जाती हैं। ये जाति, पंथ तथा धर्म के नाम पर लोगों को बाँटते हैं ताकि कानून-व्यवस्था भंग करके, राजनैतिक लाभ प्राप्त किया जा सके। सत्ता में आने के लिये, उत्तर भारत के कई राज्यों में भाजपा ने यही किया है। वे तमिलनाडु में भी उसी सूत्र तथा तौर-तरीके को काम में ले रहे हैं।

नाबालिग से ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मौजूद थे।"

बाद में इन लोगों ने मेरे को धमकी दी कि, तेरी फोटो अश्लील बना दी है हम वायरल कर देंगे तू कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इन लोगों ने मेरी वीडियो बनाई और सभी ने मेरा बलात्कार किया मैं कई घंटों तक बेसुध पड़ी रही। उसके बाद में अपने घर आई इन सभी द्वारा मुझे धमकी दी कि, अगर कोई भी बात बताई तो वीडियो वायरल हो जाएगा। मैं डर गई धीरे-धीरे यह लोग मुझसे पैसे ऐंठने लगे इसके बाद पीड़िता ने 3 जनवरी व 6 अप्रैल को भी बुलाकर बलात्कार करने की घटना दर्ज करवाई है।

'ऊंट के ऊपर अब...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनाव में प्रत्याशी नहीं होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी यह निर्णय लेंगी कि राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन होगा।

अशोक गहलोत अब भी जोधपुर हाउस में ठहरे हुए हैं। उन्होंने शांति धारीवाल और महेश जोशी से कहा था कि वे दिल्ली आ जाएं। ये दोनों दिल्ली के लिए रवाना हुए, लेकिन इस दौरान बीच में कहीं महेश जोशी को यह संदेश प्राप्त हुआ कि वे कांग्रेस विधायक दल के चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दें।

जोशी पुन: जयपुर के लिए लौट गए, जहां उन्होंने कुछ विधायकों के साथ मीटिंग कर सलाह-मशविरा किया। चीफ व्हिप ही कांग्रेस विधायक दल सदस्यों की मीटिंग आयोजित करता है और इसमें कुछ दिन पूर्व मिली नाकामयाबी के बाद नेतृत्व मीटिंग आयोजित करने के मामले में महेश जोशी पर विश्वास नहीं करना चाहता।

किसी भी सूरत में, महेश जोशी के खिलाफ विधायकों को गुमराह करने और सोनिया गांधी के आदेश को लागू करने से इंकार करने को लेकर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की गई है।

सूत्र कहते हैं कि प्रियंका गांधी ने भी इन खबरों की प्रतिक्रिया में गहलोत की खिंचाई की कि उनके (गहलोत) आदमी कह रहे थे कि सचिन पायलट, प्रियंका का कैंडिडेट है। प्रियंका ने यह कहते हुए उनकी भर्त्सना की कि निर्णय हाई कमान, यानि की सोनिया गांधी द्वारा लिए जाते हैं। अपना नाम बीच में घसीटने पर उन्होंने गहलोत को आड़े हाथ लिया।

उम्मीद है कि सचिन पायलट की संभवत: देर रात्रि सोनिया गांधी से मुलाकात होगी जिसमें जयपुर के घटनाक्रमों को अंतिम रूप देने पर चर्चा की जाएगी।

अविश्वास तो पूरा है। एक सीनियर नेता ने कहा कि अशोक गहलोत को पूर्ण बगावत की कीमत चुकानी होगी।

सी.एल.पी. की ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

मीटिंग के लिए सहमति प्रदान की है।

कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि यह फिर सोनिया पर निर्भर होगा कि गहलोत को अपने पद पर बने रहने दिया जाए या नहीं अथवा उनके द्वारा मनोनीत किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जाए।

भाजपा और बी.जे.डी. चुनाव की जॉइन्ट रणनीति बनायेंगे

भुवनेश्वर, 29 सितंबर (वार्ता)। भाजपा ने देश में आम चुनाव 2024 से पहले ओडिशा में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए गुरुवार को पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा यहां पहुंचे। नड्डा यहां दो दिवसीय दौरे पर आए हैं। वर्ष 2020 में पार्टी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद नड्डा की यह राज्य की पहली यात्रा है। नड्डा के यहां बीजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने के बाद उन्हें पार्टी की राज्य ईकाई के मुख्यालय ले जाया गया जहां भाजपा युवा मोर्चा ने वृहद बाइक रैली का आयोजन किया। इसके बाद वह यहां जनता मैदान पर बूथ लेवल के पार्टी कार्यकताओं को संबोधित करेंगे और बाद में 2024 के चुनाव को लेकर रणनीति के संबंध में सांसदों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से बात करेंगे।

आज शाम को पार्टी अध्यक्ष पुरी के लिए रवाना होंगे और वहां रात्रि विश्राम करेंगे।

राहुल की भारत जोड़ो यात्रा की...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

संदिग्ध नहीं मानी गई थी।

लेकिन यात्रा की असली परीक्षा आज (शुक्रवार) को शुरू होनी है, जब राहुल गांधी को, कार्यक्रमानुसार, "शत्रु के क्षेत्र" में प्रवेश करना है। लेकिन कर्नाटक में भी, छोटे-बड़े ऐसे सैकड़ों संगठनों का समर्थन उन्हें मिला है, जो समाजवादी वैदिके के झंडे तले आ गये हैं जिसका नेतृत्व बेंगलुरू की यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज़ के सेवानिवृत प्रोफेसर प्रकाश कम्मार्दी करने वाले हैं।

कर्नाटक सरकार से जो अपेक्षा की जा सकती थी, उसका नमूना वरिष्ठ कांग्रेस नेता डी.के.शिवकुमार की जाँच के रूप में देखा जा सकता है, जबकि कांग्रेस के 'पे सीएम' जैसे सृजनात्मक तथा आकर्षक अभियान में बताये गये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जन-अदालत की संवीक्षा हो चुकी थी। ज्ञातव्य है कि शिव कुमार पार्टी के मुख्य संकटमोचक है तथा पार्टी के सामने जब-जब भी विरोधियों की और से विधायकों को छीने जाने का संकट आया हैं, पार्टी ने उन्ही की तरफ देखा है, अपने बचाव के लिये उन्हीं के पास गई हैं।

सी.वी.आई. अधिकारियों ने गुरूवार को उनसे जुड़े हुये कई ठिकाने तथा दस्तावेज खँगाले। ये सम्पत्तियाँ शिवकुमार की बताई जाती हैं।

स्वतन्त्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब, भारत जोड़ो यात्रा के कर्नाटक में प्रवेश से ठीक पहले, कर्नाटक के इस वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ की जा रही यह कार्यवाही, एक हताशा ही तो है।

शिव कुमार की सम्पत्तियों की जाँच के समाचार की प्रतिक्रिया में, राजनैतिक विश्लेषक सुमन्त सी.रमन ने एक ट्वीट में कहा, "भारत जोड़ो यात्रा को कर्नाटक में कल प्रवेश करना है। यह सब कुछ भविष्यवाणी के अनुरूप, अर्थात अपेक्षित ही हो रहा है।"

विश्लेषकों ने अब यह जानने की इच्छा जाहिर करना शुरू कर दिया है कि क्या सी.बी.आई., ई.डी. तथा आई.टी. जैसी केन्द्रीय जाँच एजेंसियों की कार्यवाहियों का वांछित प्रभाव एवं परिणाम प्राप्त हो रहा है। एक विश्लेषक ने कहा कि सड़क पर चलाता हुआ एक आम आदमी भी अब इन जाँचों को संदेह से देखने लगा है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार की इन एजेंसियों की कार्यवाहियाँ अब "अपेक्षाकृत कम तथा मामूली परिणाम ही लाती" दिखाई दे रही है क्योंकि ये सब राजनीति-प्रेरित मानी जा रही हैं।

सोशल मीडिया लोगों की इस बदलती हुई सोच को प्रदर्शित करता दिखाई दे रहा है, जैसा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर लोगों की टिप्पणियों से जाहिर हो रहा है। लोग यह जानना चाह रहे हैं कि इन जाँच एजेंसियों के निशाने पर केवल विपक्षी दलों के लोग ही क्यों आ रहे हैं।

कांग्रेस ने कर्नाटक की जनता को केन्द्रीय एजेंसियों के इस "विरोधी रूख" के लिये पहले ही तैयार कर दिया है तथा उन्हें समझा दिया है कि इन जाँचों का उद्देश्य कांग्रेस की छवि को खराब करना है। ज्ञातव्य है कि कर्नाटक के विधान सभा चुनावों में अब एक साल से भी कम समय रह गया हैं।

कांग्रेस के नेता इस कार्यवाही के पीछे छिपे भाजपा की कुंठा तथा डर को समझ चुके हैं क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को आम जनता का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है तथा इसलिये भाजपा इसे बदनाम करने के लिये कटिबद्ध हैं।

एक राजनैतिक विश्लेषक ने कहा, "लेकिन यह सब कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी राजस्थान के पार्टी संकट जो शुद्ध रूप से उन्हीं के करे-धरे का नतीजा है, से कैसे निबटते हैं।" उहोंने आगे कहा कि "अब इसके आगे, यह लड़ाई और दिलचस्प हो जायेगी क्योंकि यात्रा के आगे के अधिकांश रास्ते में यह कांग्रेस बनाम भाजपा के रूप में सीधी लड़ाई का रूप ले लेगी, क्योंकि इसके बाद, राहुल गांधी प्रमुख भाजपा-शासित राज्यों-महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश छोटे-छोटे हिस्सों से गुजरेंगे।"

विधायक दल की समानान्तर ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गया था कि आलाकमान की ओर से प्रभारी महासचिव को स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि अनुशासनहीनता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

इसके बाद ही माकन की रिपोर्ट पर तीन नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी होते ही यह स्पष्ट हो गया था, कि इस झमेले में भले ही अशोक गहलोत की सीधी भूमिका ना रही हो, लेकिन उनके नजदीकी नेताओं की ओर से समानांतर बैठक बुलाना कहीं ना कहीं उनकी सहमति के बिना संभव नहीं हो सकता था। इसके बावजूद शांति धारीवाल और धर्मेंद्र राठौड़ सहित अन्य नेता अजय माकन को ही गलत ठहराने में जुट गए और सार्वजनिक बयानबाजी करने लगे। यह बात भी मुख्यमंत्री गहलोत खेमे के खिलाफ गई। ऐसे में जहां बीच का रास्ता निकल सकता था, वहां प्रभारी की रिपोर्ट के आधार पर आलाकमान की ओर से स्पष्ट संकेत दे दिया गया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यदि दिल्ली आएं तो आलाकमान का आदेश मानने की स्थिति में ही आएं।

गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे, उससे पहले ही मुकुल वासनिक के जरिए उन्हें फिर संदेश पहुंचा दिया गया था कि पार्टी आलाकमान उनकी सफाई सुनने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। यही कारण है कि बाहर आकर खुद अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से माफी मांग ली है।

अशोक गहलोत का माफी मांगना और खुद बाहर आकर मीडिया से कहना, राजनीतिक रूप से बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि जो गहलोत 3 दिन पहले तक कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए आलाकमान की पहली पसंद बने हुए थे, उनके लिए 25 सितंबर की रात की घटना ने सारे घटनाक्रम को बदल कर रख दिया।

दूसरी ओर प्रभारी महासचिव अजय माकन की भूमिका इस पूरे प्रकरण में आलाकमान के प्रति बेहद सकारात्मक रही और उन्होंने राजस्थान के घटनाक्रम को लेकर पल-पल की जानकारी आलाकमान को लगातार दी। इतना ही नहीं इस घटनाक्रम से पहले भी सरकार को लेकर विधायकों और अन्य नेताओं में जो नाराजगी थी, राजनीतिक नियुक्तियों के दौरान जो घटनाक्रम हुए और उनसे कांग्रेसजन नाराज थे, इस बारे में भी अजय माकन पहले ही कांग्रेस आलाकमान को बता चुके थे। ऐसे में यह घटनाक्रम होते ही अजय माकन की ओर से आलाकमान को पहले बताई गई तमाम घटनाएं सच साबित हुई। उसी आधार पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से ना सिर्फ बाहर हो गए, बल्कि आलाकमान का अब तक उन पर जो भरोसा था वह भी समाप्त हो गया।

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब एक-दो दिन में ही राजस्थान में विधायक दल की बैठक फिर होगी और उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पारित करके विधायक दल का नेता चुनने के लिए आलाकमान को सर्व सम्मति से कहा जाएगा। इसके बाद में राजस्थान में मुख्यमंत्री पद के लिए सोनिया गांधी फैसला करेंगी। पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भी यही कहा है कि एक-दो दिन में राजस्थान का मसला सुलझा लिया जाएगा और विधायक दल की बैठक के बाद में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी नए नेता के नाम का ऐलान करेंगी।

प्रधानमंत्री मोदी की निंदा के मामले में मुकदमा दर्ज

इंदौर, 29 सितम्बर। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर गलत बयानबाजी का 6 साल बाद फिर चर्चा में है। खबर है कि मामले में साल 2016 में शिकायत दर्ज कराने वाले शख्स को 6 साल बाद बुधवार को बयान देने के लिए बुलाया गया। आरोप लगाए गए थे कि एक रैली के दौरान पीएम मोदी को लेकर अपशब्द कहे गए थे। शिकायतकर्ता ने मामले में कांग्रेस नेता पर आरोप लगाए थे, जो अब विधायक हैं।

मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इकबाल मैदान का बताया जा रहा है। शिकायत दर्ज कराई गई थी कि हजारों लोगों की मौजूदगी में पीएम को लेकर आपत्तिजनक बयान दिए गए थे। शिकायत करने वाले शमसुल हसन बल्ली उस दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे और अब सनुक्त संघर्ष मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ राज्य सरकार को भी ऑडियो-वीडियो सबूत के साथ शिकायत भेजी थी।

बयान दर्ज कराने के बाद उन्होंने कहा, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर मंच से अपशब्द कहे गए। कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है, वह हमारे चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। जो कोई भी उनके खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। मैंने तब राज्यपाल, डीजीपी, मुख्यमंत्री को शिकायत भेजी थी। लेकिन श्यामला हिल्स से पुलिस स्टेशन आने में 6 साल का समय लग गया।

खबर है कि ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल का पहले बार कॉन्क्लेव भोपाल में आयोजित हुआ। इसमें शामिल होने के लिए देशभर से 300 डेलीगेट्स पहुंचे थे। कॉन्क्लेव के बाद 29 अक्टूबर को एक सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन इकबाल मैदान में हुआ, जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। बल्ली के अनुसार, वह आरिफ मसूद थे, जिन्होंने पीएम मोदी के लिए मंच से अपशब्द कहे थे।

भाजपा प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी का कहना है, यह प्रशासन की प्रक्रिया है। कानून अपना काम करेगा। दोषियों को सजा मिलेगी। शिकायतकर्ता को बुलाने में 6 साल लग गए, केवल इसलिए ही हम यह नहीं कर सकते कि लापरवाही की गई थी।

कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने कहा, मंच पर दर्जनों लोग थे, लेकिन आरिफ मसूद कांग्रेस से विधायक हैं, उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है। यह विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास है।

नीतीश कुमार को कड़ी टक्कर मिलेगी मुख्यमंत्री के.सी.आर. से

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दावेदारी के बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (के.सी.आर) राष्ट्रीय दल बनाने जा रहे हैं। हैदराबाद में 5 अक्टूबर को दशहरा के मौके पर राष्ट्रीय दल की रणनीति सार्वजनिक कर दी जायेगी। इसके लिए कार्यक्रम की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। के.सी.आर की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के नाम और उसके संरचना को लेकर पहले से ही काम किया जा रहा था। अब विजय दशमी के मौके पर राष्ट्रीय पार्टी की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी।

पार्टी नेताओं का कहना है कि, किसी भी काम की शुरुआत के लिए दशहरा एक शुभ दिन होता है। ऐसे में इसी दिन राष्ट्रीय पार्टी की घोषणा की औपचारिक घोषणा की जाएगी। दशहरा के दिन तेलंगाना भवन में दोपहर बाद टी.आर.एस. विधायक दल की बैठक होगी।

जिसमें मुख्यमंत्री के.सी.आर. की ओर से राष्ट्रीय पार्टी के गठन को लेकर वन लाइन प्रस्ताव पारित किया जाएगा।

तेलंगाना भवन में विधायक दल की बैठक के बाद टी.आर.एस. की राज्य कार्यकारिणी समिति की ओर से भी एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इस दिन पार्टी के सभी सांसदों, विधायक, एम.एल.सी. और राज्य स्तर के सीनियर नेताओं के साथ-साथ पार्टी के सभी सीनियर नेताओं को तेलंगाना भवन आने को कहा गया है। इसके बाद के.सी.आर. राष्ट्रीय पार्टी के शुभारंभ की घोषणा करेंगे और पार्टी के नेताओं को एजेंडे के बारे बताएंगे। पार्टी नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री उसी बैठक में टी.आर.एस. के राष्ट्रीय समन्यवकों की भी घोषणा करेंगे।

हालांकि, नई राष्ट्रीय पार्टी का नाम अभी तक गुप्त रखा गया है, लेकिन पार्टी नेताओं ने संभावना जताई है कि उनकी राष्ट्रीय पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्र समिति (बी.आर.एस.) हो सकती है। अभी तक इस बात को लेकर भी स्थिति साफ नहीं हो पाई है कि के.सी.आर. अपनी पुरानी पार्टी टी.आर.एस. को भंग करेंगे या फिर बी.आर.एस. में उसका विलय करेंगे या फिर टी.आर.एस. भी अपने अस्तित्व में रहेगी।

राष्ट्रीय पार्टी के शुभारंभ को देखते हुए टी.आर.एस. की ओर से देश के सभी प्रमुख राज्यों में प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई जा रही है। देशभर के प्रमुख शहरों में होर्डिंग के साथ-साथ प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर विज्ञापन देने की भी तैयारी चल रही है। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश का नेता के.सी.आर. का नारा देश के कोने-कोने में ले जाया जाएगा।

सऊदी अरब युनिवर्सिटी में भी योग के प्रोफैशनल कोर्सेज़ शुरु होंगे

रियाद, 29 सितम्बर। सऊदी अरब ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में योग की शुरुआत की है। इस सिलसिले में सभी यूनिवर्सिटीज के प्रतिनिधियों के लिए सोमवार को एक वर्चुअल लैक्चर का आयोजन किया गया। इसके जरिए लोगों को योग को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट्स के पास भी यूनिवर्सिटी कैंपस में विभिन्न योगासनों को करने का विकल्प मौजूद रहेगा।

लेक्चर के दौरान योग के मेंटल और फिजिकल स्वास्थ्य पर असर के बारे में बताया गया। साथ ही स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कांपटीशन का हिस्सा बनने के लिए प्रोफेशनल योगासन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की योजना पर भी बात की गई।

सऊदी स्पोर्ट्स फेडरेशन और सऊदी योगा कमेटी ने रियाध में यह आयोजन किया था। सऊदी गैजेट के मुताबिक इसमें छात्र-छात्राओं दोनों शामिल होंगे। इस रिपोर्ट के मुताबिक योगा रेफरी के क्वॉलीफिकेशन कोर्स के लिए पहला बैच सऊदी से भारत भी पहुंच चुका है।

चर्चित जज मुरलीधर मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। सुप्रीम कोर्ट कोलीजियम ने उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस. मुरलीधर (61) का मद्रास हाई कोर्ट स्थानांतरण करने की सिफारिश की है। मद्रास हाई कोर्ट में पिछले कुछ समय से एक के बाद एक कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे हैं। जस्टिस मुरलीधर चीफ जस्टिस डी. राजा का स्थान लेंगे।

मुरलीधर दिल्ली हाई कोर्ट जज के रूप में वर्ष 2020 में तब विवादास्पद बन गए थे जब उत्तर पूर्व दिल्ली में हुए दंगों में उन्होंने लापरवाही बरतने को लेकर दिल्ली पुलिस की आलोचना की थी और इसके बाद उनका आधी रात को ही तबादला कर दिया गया था। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट जाने से पूर्व उन्होंने अपने तबादले के पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया था।

जस्टिस मुरलीधर मद्रास हाई कोर्ट के लिए नए नहीं हैं क्योंकि उन्होंने सितम्बर 1984 में अपनी कानूनी प्रैक्टिस यहीं से शुरू की थी। उसके बाद वे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पेशेवर वकील बन गए थे। दिल्ली में वे जी. रामास्वामी के जूनियर थे जो बाद में भारत के अटॉर्नी जनरल बने।

जो केस उन्होंने नि:शुल्क लड़े, उनमें भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के केस, ऐसी दर्दनाक स्थितियों के केस, जिनमें कथित मानसिक रोगियों को जेलों में बंद कर दिया गया था और नर्मदा बांध विस्थापितों के केस शामिल हैं। जनहित के कई केसों और फांसी की सजा प्राप्त लोगों के केसों में उन्हें न्याय मित्र नियुक्त किया गया था। मुरलीधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और भारतीय चुनाव आयोग में अधिवक्ता रहे और दिसम्बर 2002 से मई 2006 तक विधि आयोग के अंशकालिक सदस्य रहे।

दिल्ली हाई कोर्ट में करीब 14 वर्षों तक जज रहने के दौरान उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण फैसले सुनाए। एक जज के रूप में उन्होंने कोर्ट के संबोधन के लिए "माई लॉर्ड" और "योर लॉर्डशिप" के प्रयोग को अनुचित बताया और कोर्ट रजिस्ट्री को निर्देशित किया कि वह उनके कोर्ट की डेली कॉज़लिस्ट में एक टिप्पणी संलग्न कर वकीलों से अनुरोध करें कि वे जजों को माई लॉर्ड तथा योर लॉर्डशिप का संबोधन करने से परहेज करें।

जस्टिस मुरलीधर 29 मई 2006 से 5 मार्च 2020 तक दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे और उसके बाद 6 मार्च 2020 से 3 जनवरी 2021 तक पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज रहे। उन्होंने 1 जनवरी 2021 को उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली थी।

गैस रिसाव के बाद 59 मजदूरों की हालत गम्भीर

अलीगढ़, 29 सितम्बर। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में थाना रोरावर क्षेत्र के तालसपुर इलाके में गुरुवार सुबह मीट फैक्ट्री में अमोनिया गैस के रिसाव होने से अफरा तफरी मच गई। 70 से अधिक मजदूरों की हालत बिगड़ गई है। 59 को जेएन मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इनमें महिलाएं भी शामिल हैं। इस मामले में मीट फैक्ट्री के छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

59 मजदूरों को जे.एन. मैडिकल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम युनिर्वसिटी में भर्ती कराया गया है। सीओ प्रथम व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर है। डी.एम. इंद्र विक्रम सिंह व एस.एस.पी. कलानिधि नैथानी मैडिकल पहुंच गए।

डी.एम. इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मजदूरों की हालत स्थिर है। प्राथमिक उपचार दिलाया जा रहा है। सभी संबंधित विभागों को आदेश दे दिए हैं। मीट फैक्ट्री अलदुआ में हादसा अमौनिया गैस पाइप फटने से हुआ है। मामले की जांच की जा रही है। 59 मजदूरों को जे.एन. मैडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। सभी की हालत अभी तक ठीक है। फैक्ट्री के मालिक की पहचान हाजी जहीर के रूप में की गई है। मीट फैक्ट्री अल दुआ के छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया है।

अल दुआ फैक्ट्री में अमौनिया गैस रिसाव की घटना के बाद जे.एन. मैडिकल कालेज की इमरजेंसी सेवा में मजदूरों के स्वजनों की भीड़ लगना शुरू हो गया।

देश में पिछले 24 घंटे में ग्यारह मरीजों की मौत

नयी दिल्ली 29 सितंबर (वार्ता) देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी से 11 मरीजों की मौत हो गयी, जिससे देश भर में अब मृतकों की संख्या बढ़कर 528611 हो गई और मृत्यु दर 1.19 फीसदी पर बरकरार है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि सुबह सात बजे तक 218.17 करोड़ टीके दिये जा चुके हैं और पिछले 24 घंटे में कोविड-19 सक्रिय मामलों के आंकड़ों में 229 की कमी आई है, जिससे अब संक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 40750 रह गया और दैनिक संक्रमण दर 1.35 प्रतिशत है। सक्रिय मामलों की दर 0.10 प्रतिशत है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में कोरोना महामारी संक्रमण से ग्रसित 4,272 नये मरीजों की पुष्टि हुई है, जिससे अब संक्रमित मरीजों का कुल आंकड़ा बढ़कर 4,45,83,360 हो गया। इसी अवधि में कोरोना वायरस से 4474 लोगों को मुक्ति मिली है और देश भर में अब तक कुल 44013999 लोगों की सेहत में सुधार हो चुका है और स्वस्थ दर बढ़कर 98.72 प्रतिशत हो गयी है।

पिछले 24 घंटों में 3,16,916 कोविड परीक्षण किए गये हैं। जिसके बाद कुल परीक्षणों की संख्या 89.47 करोड़ से अधिक हो चुकी हैं।

पिछले 24 घंटों में सात राज्यों और दो केन्द्र शासित प्रदेश में कोराना के मामलों में बढ़ोतरी हुई है और अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों में इसके मामलों में कमी देखी गयी है।

इसी दौरान केरल में भी 82 सक्रिय मरीज पाए जाने से, अब इनकी संख्या बढ़कर 12195 हो गयी है। इस वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 6719562 हो गया है और मृतकों का आंकड़ा 71134 पर स्थिर है।

पिछले 24 घंटे में राष्ट्रीय राजधानी में छह मामले बढ़े हैं, जिससे संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 392 हो गया है। इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या 1976314 पर स्थिर बनी रही। इसी अवधि में मृतकों का आंकड़ा 26501 पर बरकरार है।

तमिलनाडु में कोरोना वायरस ने फिर गति पकड़ी, जिससे यहां कोरोना के 26 संक्रमित मामले बढ़कर 5498 हो गए हैं और इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या 3538507 हो गयी है। और मृतकों का संख्या 38046 पर बरकरार है।पश्चिम बंगाल में कोरोना के 71 मरीजों की संख्या बढ़ने से, अब यह संख्या 3170 हो गयी है और इस बीमारी से निजात पाने वालों की संख्या 2089302 हो गयी है। राज्य में इसी दौरान दो मरीजों की मौत होने से मृतकों की संख्या 21503 तक पहुंच गई।

उत्तरप्रदेश में कोरोना महामारी के 28 नए मामले आने से संक्रमितों की संख्या 527 हो गई और स्वस्थ लोगों का आंकड़ा बढ़कर 2101983 हो गया है, जबकि मृतकों की संख्या 23620 पर बरकरार है।

महाराष्ट्र में कोरोना के 73 मामले घटे हैं, जिससे अब राज्य में मरीजों का कुल आंकड़ा घटकर 3429 रह गया है। इस वायरस से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़कर 7968736 हो गया है और मृतकों का आंकड़ा 148336 तक पहुंच गया है।

राजस्थान में पिछले 24 घंटे में कोरोना महामारी के 67 मामलों में गिरावट आने से अब राज्य में घटने वालों की संख्या 499 रह गई है और इस महामारी से निजात पाने वालों की संख्या 1302893 पर ही बरकरार रही। राज्य में कोरोना महामारी से एक मरीज की जान जाने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 9641 हो गया।

गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 संक्रमण के 53 मामले घटकर 900 रह गए हैं और अब तक 1262618 लोग इस महामारी से मुक्त हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में एक मरीज की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 11034 पर बरकरार है।

पुडुचेरी में भी 28 मामले घटने से संक्रमितों की संख्या 368 रह गई है। इस महामारी से निजात पाने वालों की कुल संख्या 172173 पर स्थिर बनी रही।

आर्मेनिया बनेगा भारतीय मिसाइलों का बड़ा खरीददार

नई दिल्ली, 29 सितम्बर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने के लिए भारत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ना केवल अपने लिए बल्कि दूसरे देशों को भी रक्षा सामग्री निर्यात करने के लिए हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। इस बीच भारत और आर्मीनिया के बीच बड़ी डील हुई है। आर्मीनिया अपने पड़ोसी अजरबैजान से लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद से जूझ रहा है। ऐसे में वह अपनी सेना को मजबूत करने के लिए भारत का सहारा ले रहा है। भारत बड़ी मात्रा में हथियार और रक्षा उपकरण आर्मीनिया को सप्लाई करेगा।

जानकारी के मुताबिक यह काफी बड़ी डील है। डील लगभग 2 हजार करोड़ रुपये की हो सकती है। बता दें कि भारत ने अपनी नीतियों में सुधार किया है और हथियारों के निर्यात बढ़ाने पर अहम फैसला किया है। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत आर्मीनिया को पिनाक मल्टी बैरेल रॉकेट लॉन्चर भी देगा जो कि भारत की सेना पहले से ही इस्तेमाल कर रही है।

ज्यादातर हथियार ऐसे हैं जिनकी डिजाइन डीआरडीओ ने बनाी है और अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां इनका उत्पादन कर रही हैं। भारतीय सेना ने हाल ही में 6 अतिरिक्त पिनाक रेजिमेंट का ऑर्डर दिया है। वहीं इसकी रेंज बढ़ाने पर भी काम चल रहा है। डील के मुताबिक भारत आर्मीनिया को एंटी टैंक रॉकेट भी सप्लाई करेगा। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है कि भारत आर्मीनया को रक्षा उपकरण सप्लाई कर रहा है। साल 2020 में भारत ने चार स्वाति रडार आर्मीनिया को दिए थे जिनकी कीमत 350 करोड़ रुपये थी।

भारतीय सेना के द्वारा डिजाइन किए गए ये रडार रॉकेट, मिसाइल, मोर्टार को ट्रैक करने में सक्षम थे। इन रडार को भारत ने भी पाकिस्तान और चीन की सीमा पर तैनात कर रखा है। बता दें कि भारत ने 2025 तक 35 हजार करोड़ रुपये की रक्षा सामग्री को निर्यात करने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल लगभग 13 हजार करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908